

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 116/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/167

दायर दिनांक :- 01.09.2021

निर्णय दिनांक :- 24.01.2025

1. सुरजकंवर पुत्री गजेसिंह पत्नी गैनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दो का बास देणोक तहसील आउ जिला फलोदी
2. पेम्पकंवर पुत्री गजेसिंह पत्नी रेंवतसिंह जाति राजपूत निवासी मूजासर तहसील लोहावट जिला फलोदी

अप्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. नारायणीदेवी पत्नी परमसुख जाति सुथार निवासी सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मूलचंद पुत्र परमसुख जाति सुथार निवासी सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3. पुष्पा पुत्री परमसुख पत्नी आवडलाल जाति सुथार निवासी उजलां तह. पोकरण जिला जैसलमेर
4. गीता पुत्री परमसुख पत्नी भंवरलाल जाति सुथार निवासी उजला तह. पोकरण जिला जैसलमेर
5. इलाहाबाद बैंक शाखा बारू (सिंहड़ा) जरिये शाखा प्रबन्धक बारू

प्रार्थी/प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता**



उपस्थित :- 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता
अप्रार्थीगण/वादीगण

2 श्री जगदीशचन्द्र विश्णोई अधिवक्ता
प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4

--:: निर्णय ::--

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीगण के पिता गजेसिंह के नाम वादग्रस्त भूमि थी। गजेसिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमि वादीगण एव उनकी माता के नाम विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। वादीगण एवं उनकी माता के द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रतिफल लेकर विधिवत रूप से प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया तथा भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया, उसके पश्चात अभी वादीगण एव उनके परिवार के सदस्य के मन में बदनीयति आने के कारण यह दावा प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वर्तमान में जमीन के भाव बढ गये है। पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार में खाने कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होने से उक्त जमीन बेचान की गई थी। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 287 का बेचान वादिनी एवं उनकी माता द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं अगुंष्ट निशान करके बेचान किया था। प्रतिफल की राशि प्राप्त की थी एवं भौतिक रूप से कब्जा शैतानसिंह वगैरा को सौंप दिया था तथा अन्य प्रतिवादीगणों ने कुछ भूमि गजेसिंह के वारिसान वादीगण से सीधे खरीद की तथा कुछ भूमि शैतानसिंह वगैरा से खरीद की, जिसके बाद खरीददार उक्त भूमि पर रहवासी मकान व ढाणी टांका बनाकर वर्षों से रह रहे है। उक्त दावा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के वाद को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है जबकि वादीगण द्वारा

**सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)**

प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि का बेचाननामा निष्पादित कर भौतिक रूप से कब्जा सौंप दिया था। वादीगण द्वारा भूमि का बेचाननामा दावे में एडमीट किया गया है कि इसके बाद यह दावा लेकर आये है कि भूमि के बेचाननामा में भूलवंश खसरा नम्बर गलत लिख दिये है इससे यह साबित होता है कि वादीगण के द्वारा बेचान अवश्य किया गया तथा उसके खसरा नम्बर सही करवाने की जिम्मेदारी वादीगण के चाचा डूगरसिंह को दी गयी थी। दावे में डूगरसिंह के द्वारा धोखा करना लिखते है तथा दूसरे दावे में खसरा नम्बर दुरुस्त करवाने की जिम्मेदारी देते है। ऐसे आधार लेकर किया गया दावा इस न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है। खसरा नम्बर दुरुस्त एवं बेचाननामा निरस्त करने के दावे का सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिर्फ सिविल न्यायालय को है। इस कारण उक्त वाद सव्य खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर जवाब में बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम थी, और देहान्त होने पर वादीगण व उनकी माता के नाम जरिये विरासत दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं उसकी माता के द्वारा प्रतिवादीगण कोई प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं करवाया और न वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया। वादीगण का वाद कतई बदनीयति और वादग्रस्त भूमि की कीमतें बढ़ने के कारण पेश नहीं किया है। विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर, अगुष्ट निशान करके प्रतिफल राशि प्राप्त कर भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त एवं रहवासी मकान, ढाणी व टांका नहीं है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का जब कोई विक्रय विलेख ही किसी के पक्ष में लिखवाया जाकर निष्पादित नहीं करवाया तो कूटरचित फर्जी विक्रय पत्र को शुरु से शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने और खातेदारी की घोषणा का वाद क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। वाद किसी भी तरह विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वाद सुनवाई का राजस्व न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को कतई नहीं है। वाद पूर्णरूपेण पोषणीय है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कोई विक्रय-पत्र निष्पादित करवाया जाना स्वीकार नहीं किया गया। वादीगण द्वारा अपने खातेदारी की वादग्रस्त भूमि का कोई मुख्तयारनामा अपने चाचा डूगरसिंह को कभी भी नहीं दिया। वाद कूटरचित फर्जी दस्तावेज पर होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। प्रार्थना पत्र अनायास ही वाद को लम्बा करने की गरज से पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण गजेसिंह की पुत्रियां है। वादीगण की माता व पिता के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादीगण को बेचान की गयी थी उसी दिन प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा-काश्त, ढाणी व मकान निर्मित है। वादीगण स्वयं द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान किया गया है और वादीगण स्वयं द्वारा की गई बेचान की भूमि पर पुनः वाद पेश करना विधि द्वारा वर्जित है। विक्रय पत्र में रकबा व खसरा दर्ज हो जो बाद में गलत कैसे हो सकता है। वादीगण ने उक्त बेचाननामा को वाद पत्र में स्वीकार किया है, जिसका निस्तारण सिविल न्यायालय से

24/10/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया जाना है। विक्रय-पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो विक्रय-पत्र को शुद्ध करवाना चाहिए। वादीगण ने प्रतिवादीगण के अलावा शेष भूमि जो परिवार को बेचान की गयी जो सही है लेकिन अन्य काश्तकारों को बेचान की गयी वो गलत है। सम्पति अन्तरण अधिनियम 100 रुपये से अधिक की संपत्ति पर लागू होता है। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण स्वयं के कथन है कि उन्होने कोई बेचान प्रतिवादीगण को नहीं किया है। उक्त बेचान 90 रुपये के स्टाम्प पर किया गया है जो रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना-पत्र के साथ कोई विक्रय-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। सिविल न्यायालय से उक्त विक्रय-पत्र को निरस्त करवाये जाने हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रार्थना-पत्र के निर्णय से पूर्व न्यायालय को दावा के अभिकथनों का अवलोकन किया जाना उचित है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गयी। पत्रावली में सलग्न वाद पत्र, प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्र, जमाबंदी, अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के प्रार्थना-पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

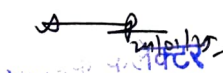
11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:-

- where it does not disclose a cause of action;
- where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;
- where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
- where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
- where it is not filed in duplicate;
- where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

- इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:-

While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.


बाम (फलोबी)



गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्राक्धान बनाये गये हैं:-

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविकता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरुस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरुस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद-पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-9 के प्राक्धानों की अनुपालना करने में विफल होना।

Object

3. सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.



4. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान *Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi* में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent. The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The

सहायक कलेक्टर
फ़रोज़पुर (पंजाब)

Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection.

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.

Role of the Court/Judge

6. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान *T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another* में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Or. VII r. 11 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."



24/1/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फतेहगढ़)

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.

Material to be considered

8. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.

Test

9. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.

Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the



सहायक कलेक्टर
राज्य (मजिस्ट्रेट)

1
5

plaint in their entirety must be held to be correct. The test is as to whether if the averments made in the complaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed. In *Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.*⁵ the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The complaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words.

How to read and examine the complaint

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the complaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the complaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

If on a meaningful reading of the complaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the complaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra.

A three-Judge Bench of this Court in *State of Punjab v. Gurdev Singh*,¹³ held that **the Court must examine the complaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the complaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted**

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the complaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the complaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities.

Essence

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330/2010 उनवान *Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Chand* में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के सारांश (Essence) को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

11. Before dealing with the factual scenario, the spectrum of Order 7 Rule 11 in the legal ambit needs to be noted. The legal position in regard to Order 7 Rule 11 CPC may be summarised as below:

(i) The relevant facts which need to be looked into for deciding an application under Order 7 Rule 11 are the averments made in the plaint. The trial Court can exercise the power at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.

(ii) The basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.

(iii) The Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.

(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.



24/01/21
सहायक कलेक्टर
बाम (फलोदी)

(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.

(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.



13. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत वाद को रेस-जूडिकेटा से संबंधित विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। इस संबंध में (Barred by Law) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

Barred by Law

14. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu* में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

11. Order 7 Rule 11(d) has limited application. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.

~~सहायक कलेक्टर~~
सहायक कलेक्टर
बाम (फलोदी)

15. माननीय गद्दास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। वादीगण का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक (मुख्य न्यायाधीश) पिण्डेल, आर.ए.एस.)
बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्त्दाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. सुरजकंवर पुत्री गजेसिंह पत्नी गैनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दो का बास देणोक तहसील आउ जिला फलोदी
2. पेम्पकंवर पुत्री गजेसिंह पत्नी रेवतसिंह जाति राजपूत निवासी मूजासर तहसील लोहावट जिला फलोदी

अप्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. नारायणीदेवी पत्नी परमसुख जाति सुथार निवासी सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मूलचंद पुत्र परमसुख जाति सुथार निवासी सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3. पुष्पा पुत्री परमसुख पत्नी आवड़लाल जाति सुथार निवासी उजला तह. पोकरण जिला जैसलमेर
4. गीता पुत्री परमसुख पत्नी भंवरलाल जाति सुथार निवासी उजला तह. पोकरण जिला जैसलमेर
5. इलाहाबाद बैंक शाखा बारू (सिहड़ा) जरिये शाखा प्रबन्धक बारू

प्रार्थी/प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

मुकदमा संख्या :- 116/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मूलचन्द सुथार प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)

बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।